

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
लोक सभा
05.04.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5374 का उत्तर

रेलवे का विद्युतीकरण कार्य

5374. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्रीमिती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री जे. सेल्वम:

श्री कुलदीप राव शर्मा:

श्री धनुष एम कुमार:

श्री सी.एन.अन्नादुरई:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण कार्य के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ग) देश में वर्तमान वर्ष, आगामी पांच वर्षों और विगत पांच वर्षों में भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण के लिए नियोजित व्यय का राज्य-वार विशेष रूप से तमिलनाडु और महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में पूरी तरह से विद्युत द्वारा रेलगाड़ियों के संचालन की अपेक्षित समय-सीमा और योजना क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का रेलगाड़ियों का परिचालन आरम्भ करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने का विचार है;
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार से निष्पादित किए जाने की संभावना है; और
- (छ) इस उद्देश्य के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेलवे का विद्युतीकरण कार्य के संबंध में 05.04.2023 को लोक सभा में डॉ. सुभाष रामराव भामरे, श्रीमिती सुप्रिया सदानंद सुले, श्री जे. सेल्वम, श्री कुलदीप राव शर्मा, श्री धनुष एम कुमार, श्री सी.एन.अन्नादुरई, श्रीमती मंजुलता मंडल, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे के अतारांकित प्रश्न संख्या 5374 के भाग (क) से (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेल ने बड़ी लाइन मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है। बहरहाल, परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे संबंधित विभागों/राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों से क्लीयरेंस, राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवा द्वारा ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्यों को पूरा करना और निष्पादन के दौरान कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों का समाधान, जो रेल मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर हैं, पर निर्भर करता है। इसलिए, परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग): रेल विद्युतीकरण के लिए निधियों का आवंटन संपूर्ण भारत आधार पर रेलवे जोन-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। संपूर्ण भारत के लिए पिछले पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (करोड़)
2017-18	3,837
2018-19	5,955
2019-20	7,145
2020-21	6,141
2021-22	6,972
2022-23	6,173
	(19.03.2023 तक)

अगले पांच वर्षों में से, योजनागत व्यय केवल वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ही उपलब्ध है जो कि 8,070 करोड़ रु. है। शेष चार वर्षों के लिए, योजनागत व्यय को आगामी वर्षों में बजट जारी किए जाने के बाद ही साझा किया जा सकता है।

(घ): पूर्ण रूप से गाड़ियों का विद्युतीकृत माध्यम में चलाया जाना विद्युतीकरण कार्य के पूरा होने और विद्युतीकृत मार्ग की तदनुरूपी कमीशनिंग पर आधारित होता है। गाड़ियों को विद्युतीकृत माध्यम चलाया जाने के लिए विद्युतीकृत मार्गों की कमीशनिंग पुनः विभिन्न कारकों जैसे संबंधित विभागों/राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों से क्लीयरेंस, राज्य विद्युत जनोपयोगी सेवा द्वारा ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्यों को पूरा करना और निष्पादन के दौरान कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों का समाधान पर निर्भर करता है, जो रेल मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर हैं।

(ङ): इस समय, भारतीय रेल में निजी गाड़ी परिचालकों द्वारा नियमित यात्री गाड़ी सेवाएं चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ): प्रश्न नहीं उठता।
